

मुंबई□ बंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि नाबालग बच्चे के संरक्षण अधिकारों पर फैसला करने के दौरान माता-पिता का धर्म वित्तीय क्षमता जैसे अन्य कारकों की अवहेलना नहीं कर सकता□

अदालत चार साल की ल□ की केपिता लस्बिन मरिंडा और उसके बुआ लु□ ला फ्रनांडीज की ओर से दायर दो अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई कर रही थी□ इसमें □ क्ल न्यायाधीश के उस फैसले के चुनौती दी गई थी जिसमें बच्ची की देखभाल की जम्मेदारी उसके नाना राजन चावला को सौंपी गई थी□ ल□ की क पति ईसाई है□ उसके मां हट्टी थी□ ल□ की केपिता अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं□ मां की मौत के बाद से बच्ची नाना-नानी के साथ रह रही है□ हालांकि, बच्ची केपिता के निर्देश पर उसके □ करशितेदार ने बच्ची की देखभाल की जम्मेदारी मांगने के बच्ची के नाना के दावे के चुनौती दी□ नाबालग ल□ की केपिता ने भी बच्ची की देखभाल की जम्मेदारी मांगी थी□

□ क्ल न्यायाधीश के समक्ष दलील दी गई थी कि नाबालग ल□ की केपिता ईसाई धर्म को मानते हैं जबकि उसके नाना-नानी हट्टी हैं□ यह अनुरोध किया गया कि ल□ की के नाना-नानी बच्ची को ईसाई धर्मोपदेश की शिक्षा नहीं दे सकेंगे□ हालांकि, इस दलील के हाई कोर्ट के समक्ष दायर अपीलों में नहीं पेश किया गया था और न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचू□ और न्यायमूर्ति □ ससी गुप्ते ने कहा कि ऐसा कर ठीक ही किया गया□ न्यायाधीशों ने कहा, 'अगर धर्म के पहलू के ध्यान में रखा जाता है तो भी यह स्पष्ट है कि बच्ची का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां पति ईसाई धर्म को मानता है और मां हट्टी थी□' न्यायाधीशों ने अपीलों के खारजि करते हुए कहा, 'साफतौर पर ऐसी स्थिति में माता-पिता में से □ कके धर्म के उतना महत्त्व देना बेहद अनुचित होगा, जो बच्चे के कल्याण पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारकों के संतुलन को समाप्त कर दे□'